भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1181
उत्तर देने की तारीख : **23** मार्च, 2012

साक्षर भारत कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सहायता

1181. **श्री नंद कुमार साय:**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं कौन-कौन सी हैं;

(घ) उन अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम क्या हैं जो अभी तक साक्षर भारत कार्यक्रम को सहायता देने के लिए राजी हो गए हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता से विभिन्न राज्यों में साक्षर भारत कार्यक्रम किस हद तक लाभान्वित हुआ है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ0 डी. पुरंदेश्वरी)

(क) से (ग): जी, हां। देश में प्रौढ़ शिक्षा को सुसाध्य बनाने तथा उसे बल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और विद्युत वित्त निगम लिमिटेड ने 18.01.2012 को एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है:

(i) प्रौढ़ शिक्षा में शैक्षिक और शोध संबंधी क्रियाकलाप।
(ii) साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए संयुक्त रूप से वातावरण का निर्माण तथा प्रवर्तन अभियान।
(iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास कार्यकलापों का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण।
(iv) सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त भूमि पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का निर्माण।
(v) आईसीटी अवसंरचना अर्थात प्रोजेक्टर, टेलीविजन, कम्प्यूटर और सौर ऊर्जा बैकअप उपस्कर आदि प्रदान करके प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को मॉडल प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के रूप में प्रोन्नत करना।
(vi) गोष्ठियां और अन्य आदान-प्रदान कार्यक्रम प्रायोजित करना।

(vii) साक्षरता शिक्षकों, साक्षरता प्रबंधकों, नवसाक्षरों और अन्य भागीदारों के लिए बहुविध पुरस्कारों का प्रायोजन करना।

(viii) इस समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमत अन्य कोई क्षेत्र।

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पीएफसी ने इस वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 6.60 करोड़ रूपए के बराबर वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(घ): अभी तक कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन लिमिटेड ऐसे अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं जो साक्षर भारत कार्यक्रम को सहायता देने के लिए सहमत हुए हैं।

(ड.): 2010-11 के दौरान कर्नाटक में कॉनकॉर की सहायता से 20 (बीस) मॉडल प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, कर्नाटक ने सूचित किया है कि ग्राम पंचायतों ने स्वैच्छिक रूप से इन मॉडल प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को अपनाने की पहल की है। मॉडल प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में जाने वाले लोगों की संख्या में महत्वपूर्ण अंतर देखा गया है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत के स्तर पर साक्षर भारत कार्यक्रम के प्रति अपेक्षाकृत अधिक समझ और स्वीकृति महसूस की गई है।